



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224]  
No. 224]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1995/ज्येष्ठ 5, 1917  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1995/JYAISTHA 5, 1917

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली 26 मई, 1995

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 142 के साथ पठित धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (सरकारी शोध्यों की बसूली के लिए व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की) नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (I) “अधिनियम” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

(II) “सरकारी शोध्यों” से इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से वसूल किया जाने वाला कोई शुल्क या वापसी या किसी व्यक्ति द्वारा संदेय ब्याज या शासित जो संदेन नहीं की गई है अभिप्रेत है;

(III) “प्रमाणपत्र” से अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा जारी किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(IV) “आयुक्त” से अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(V) “समुचित अधिकारी” से आयुक्त के अधीनस्थ ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्की और विक्रम के प्रयोजन के लिए और प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम के आगम के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(VI) “व्यक्तिकर्मी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अधिनियम के अधीन सरकारी शोध्य वसूलनीय है।

(VII) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य शब्दों/या पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

## अध्याय 2

## संपत्ति की कुर्की के लिए प्रक्रिया

3. प्रमाणपत्र जारी करना :— जहाँ किसी सरकारी शोध का किसी व्यतिक्रमी द्वारा संदाय नहीं किया गया है वहाँ सहायक सीमशुल्क आयुक्त, ऐसे व्यक्ति से शोध रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उसे उस आयुक्त को भेजेगा जिसकी ऐसे स्थान पर जहाँ व्यतिक्रमी किसी जंगम या स्थावरी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, या अपना बैंक खाता है अधिकारिता है।

4. सूचना जारी करना :—उपरोक्त नियम 3 में उल्लिखित प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर आयुक्त अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, व्यतिक्रमी से सूचना तामील किए जाने की तारीख में सात दिन के भीतर प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने की अपेक्षा करते हुए व्यतिक्रमी पर सूचना की तामील करने, यह संसूचित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि और व्यतिक्रम की दशा में, ऐसा अधीनस्थ अधिकारी इन नियमों के निर्बन्धनों के अनुसार प्रमाणपत्र से उल्लिखित रकम के आपन के लिए कदम उठाने के लिए प्राधिकृत है।

5. संपत्ति की कुर्की :—यदि पूर्ववर्ती प्रक्रिया नियम के निर्बन्धनों के अनुसार जारी की गई सूचना में उल्लिखित रकम का सूचना की तामील किए जाने के सात दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी व्यतिक्रमी की संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके रकम के आपन की कार्यवाही कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए, समुचित अधिकारी, जब तक व्यतिक्रमी द्वारा निरोध की लागत के साथ प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक व्यतिक्रमी की संपत्ति को अवरोध या करस्थम कर सकेगा।

## 6. कुर्की अत्यधिक नहीं होगी :—

संपत्ति के अवरोध या करस्थम द्वारा कुर्की अत्यधिक नहीं होगी अर्थात् कुर्की की गई संपत्ति जहाँ तक संभव हो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात के निकट होगी।

## 7. सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य कुर्की करना :—

अवरोध या करस्थम द्वारा व्यतिक्रमी की संपत्ति की कुर्की सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व की जाएगी अन्यथा नहीं।

## 8. संपत्ति तालिका :—

व्यतिक्रमी की संपत्ति की कुर्की के पश्चात् समुचित अधिकारी कुर्की की गई संपत्ति की एक तालिका तैयार करेगा और इसमें उस स्थान को विनिर्दिष्ट

करेगा जहाँ वहाँ रखी गई है तथा उसकी एक प्रति व्यतिक्रमी या ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रभार से संपत्ति कुर्की करस्थम की गई है, सौंप देगा।

9. कतिपय मामलों में प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना :—

(i) जहाँ किसी व्यतिक्रमी पर नियम 4 के अधीन सूचना तामील की गई है वहाँ व्यतिक्रम या उसका हित प्रतिनिधि समुचित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना अपनी किसी संपत्ति को बंधक करने, भारित करने, पट्टा पर देने या अन्यथा उसका संव्यवहार करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

(ii) जहाँ इन नियमों के अधीन कोई कुर्की की गई है वहाँ कुर्की की गई संपत्ति का या किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल कोई प्राइवेट अंतरण या परिदान कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी ऋणों के विरुद्ध शून्य होगा।

10. संपत्ति में अंश :—जहाँ कुर्की की जाने वाली संपत्ति में व्यतिक्रमी की उसकी और सह-स्वामी के रूप में अन्य का संपत्ति में अंश या हित है वहाँ कुर्की व्यतिक्रमी को अंश या हित का अंतरण करने या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करते हुए सूचना देकर की जाएगी।

11. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की :—

जहाँ कुर्की की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है वहाँ कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए सूचना देकर की जाएगी कि ऐसी संपत्ति या उस पर संदेय होने वाली कोई व्याज या लाभांश ऐसे समुचित अधिकारी के जिसके द्वारा सूचना जारी की गई है अगले आदेश के अधीन रहते हुए धारित किया जाएगा :

परन्तु जहाँ ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है वहाँ समुचित अधिकारी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच जो व्यतिक्रमी नहीं है जो किसी समनुदेशन कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी संपत्ति में हितबद्ध लेने का दावा करना है, उद्भूत होने वाले हक या पूर्वाधिकार के किसी प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

## 12. कुर्की की सूचना की तामील :—

कुर्की के आदेश की एक प्रति की तामील व्यतिक्रमी पर वैसे ही रीति में की जाएगी जो अधिनियम की धारा 153 में आदेश या विनिर्देशन का तामील के लिए विहित है।

13. कुर्की की उद्घोषणा :—कुर्की के आदेश की उद्घोषणा कुर्की की जानने वाली संपत्ति के या उसके समीप

किसी स्थान पर या डुगडुगी बजाकर या अन्य पारंपरिक रीति से की जाएगी और आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और समुचित अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका दी जाएगी।

14. कुर्की से छूट-प्राप्त संपत्ति :—(i) ऐसी सभी संपत्ति जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के द्वारा किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त है, इन नियमों के अधीन कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी।

(ii) हम वारे में कि कौनसी संपत्ति इस प्रकार छूट प्राप्ति की हकदार है, समुचित अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

### अध्याय 3

#### भाग-क

#### संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया

15. संपत्ति का विक्रय : यदि, प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम का संपत्ति के निरोध की लागत सहित संपत्ति की कुर्की किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो आयुक्त समुचित अधिकारी को व्यक्तिगत संपत्ति के सार्वजनिक नीलामी में विक्रय द्वारा, रकम की आपन की वसूली करने की कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा—

परन्तु आयुक्त सार्वजनिक नीलामी में विक्रय की जाने वाली व्यक्तिगत संपत्ति की किसी संपत्ति की बाबत आरक्षित मूल्य नियत करने के लिए और यह आदेश करने के लिए सक्षम होगा कि किसी भी बोली को केवल इस शर्त पर स्वीकार किया जाएगा कि वह ऐसे आरक्षित मूल्य से कम नहीं है।

16. किसी निगम परक्राम्य लिखतें और अंश (शेयर) :—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति किसी निगम में, कोई परक्राम्य लिखित या किसीका अंश है वहां समुचित अधिकारी, संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किए जाने का निदेश देने के बजाए ऐसी लिखित या अंश का किसी दलाल के माध्यम से विक्रय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा।

#### भाग-ख

#### स्थायर संपत्ति के विक्रय की बाबत विशेष उपबंध

17. विक्रय की उद्घोषणा :—जहां किसी स्थायर संपत्ति का विक्रय किए जाने का आदेश दिया जाता है वहां समुचित अधिकारी आशयित विक्रय की उद्घोषणा जेने की भाषा में कराएगा।

18. उद्घोषणा की विषय वस्तु :—स्थायर संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा व्यक्तिगत संपत्ति की सूचना देने के पश्चात तैयार की जाएगी और उसमें विक्रय के समय तथा स्थान का कथन होगा और उसमें यथासंभव उचित रूप से और ठीक-ठीक निम्नलिखित की बाबत विनिर्दिष्ट होगा—

- (क) विक्रय की जाने वाली संपत्ति ;
- (ख) संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हो,
- (ग) उस वसूली की रकम जिसके विक्रय का आदेश दिया जाता है ;
- (घ) वह आरक्षित कीमत, यदि कोई है, जिसके कम पर संपत्ति का विक्रय न किया जाए ; और
- (ङ) कोई अन्य बात जिसे समुचित अधिकारी संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने की दृष्टि से क्रेता के लिए जानना तात्त्विक समझता है।

19. उद्घोषणा करने का ढंग : (i) स्थायर संपत्ति के विक्रय के लिए प्रत्येक उद्घोषणा ऐसी संपत्ति के या उसके समीप किसी स्थान पर या डुगडुगी बजाकर या अन्य पारंपरिक रीति से की जाएगी और उद्घोषणा को एक प्रति संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और समुचित अधिकारी के कार्यालय के सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जाएगी।

(ii) जहां समुचित अधिकारी इस प्रकार निवेश देता है वहां ऐसी उद्घोषणा स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन की लागत विक्रय की लागत समझी जाएगी।

(iii) जहां संपत्ति अलग-अलग विक्रय किए जाने के प्रयोजन के लिए साटों में विभाजित की जाती है वहां प्रत्येक साट के लिए उद्घोषणा करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि विक्रय को समुचित सूचना, समुचित अधिकारी की राय में अन्यथा नहीं की जा सकती है।

20. वहां विक्रय अपास्त करना जहां व्यक्तिगत संपत्ति का विक्रय हित नहीं है :—

विक्रय के तीस दिन के भीतर किसी भी समय क्रेता इस आधार पर विक्रय को अपास्त करने के लिए समुचित अधिकारी को आवेदन कर सकेगा कि व्यक्तिगत संपत्ति का विक्रीत संपत्ति में कोई विक्रय हित नहीं था।

21. विक्रय की पुष्टि :—(i) जहां विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन पूर्वगामी निगम के अधीन नहीं किया जाता है या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और समुचित अधिकारी द्वारा उसे नामंजूर कर दिया जाता है, वहां समुचित अधिकारी (यदि अन्य धन की

पूरी रकम का संवाय कर दिया गया है) विक्रय को पुष्टि करने वाला आदेश करेगा और तब विक्रय पूर्ण होगा।

(ii) जहाँ ऐसा आवेदन किया जाता है और उसे मंजूर किया जाता है तथा जहाँ विक्रय रकम के निशेष और शक्ति तथा प्रभारों पर विक्रय का अपास्त करने के लिए आवेदन किए जाने की दशा में वहाँ विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर समुचित अधिकारी विक्रय को अपास्त करने का आदेश करेगा।

परन्तु कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को न दी गई हो।

22. विक्रय प्रमाणपत्र (i) जहाँ किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय इन नियमों के अधीन पूर्ण हो गया है वहाँ समुचित अधिकारी विक्रय की गई संपत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो विक्रय के समय क्रेता द्वारा घोषित किया जाता है विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा।

(ii) ऐसे प्रमाणपत्र में वही तारीख उल्लिखित होगी जिसका विक्रय पूर्ण हो गया था।

23. क्रेता का हक:—(i) जहाँ संपत्ति का विक्रय इन नियमों के अनुसार किया जाता है, वहाँ विक्रय के समय व्यक्तिक्रमी के अधिकारी, हक और हित क्रेता में निहित होंगे, चाहे संपत्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ii) जहाँ स्थावर संपत्ति का विक्रय इन नियमों के अनुसार किया गया है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है वहाँ क्रेता का अधिकार, हक और हित उस समय से उसमें निहित हुआ समझा जाएगा जब संपत्ति का विक्रय किया जाता है न कि उस समय से, जब विक्रय पूर्ण हो जाता है।

24. अनियमितता से विक्रय का दूषित नहीं होना किन्तु क्षतिग्रस्त व्यक्ति वाद ला सकेगा:

किसी संपत्ति का विक्रय करने में हुई किसी अनियमितता से विक्रय दूषित नहीं होगा किन्तु किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसी अनियमितता के कारण सारवान रूप से क्षतिग्रस्त कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए या यदि (ऐसा अन्य क्रेता है), विनिर्दिष्ट संपत्ति की वसूली के लिए और ऐसी वसूली में व्यक्तिक्रम करने पर प्रतिकर के लिए किसी सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा।

25. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने पर प्रतिषेध:—

कोई ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से किसी विक्रय के संबंध में कर्तव्य का पालन करना है;

विक्रय की गई संपत्ति में किसी हित को अर्जित करने या अर्जित करने का प्रयत्न करने के लिए बोली नहीं लगाएगा।

26. अवकाश के दिन विक्रय पर प्रतिषेध:—

किसी रविवार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सामान्य अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन जिसको राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए, जिसमें विक्रय किया जाता है, स्थानीय अवकाश अधिसूचित किया है, इन नियमों के अधीन कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।

#### अध्याय-4

##### प्रकीर्ण

27. विक्रय आगम का व्ययन:—व्यक्तिक्रमी की संपत्ति का विक्रय आगम का निम्नलिखित रीति में उपभोग किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) विक्रय आगमन का उपयोग पहले विक्रय की लागत पूरा करने के लिए किया जाएगा;
- (ख) अतिशेष का उपयोग संपत्ति के निरोध की लागत सहित नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम को पूरा करने के लिए किया जाएगा;
- (ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का उपयोग व्यक्तिक्रमी द्वारा संदेय किन्हीं अन्य सरकारी शोध्यों की वसूली के लिए किया जाएगा;
- (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, व्यक्तिक्रमी को संदेय किया जाएगा।

28. व्यक्तिक्रमी की मृत्यु होने पर प्रक्रिया:—यदि सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् किसी समय व्यक्तिक्रमी की मृत्यु हो जाती है, तो इन नियमों के अधीन कार्य-वाहियां व्यक्तिक्रमी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध जारी रखी जा सकें और इन नियमों के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो विधिक प्रतिनिधि ही व्यक्तिक्रमी हो।

[सं. 495/15/94—सी यू एस VI]

टी. प्रार. कपूर, प्रवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1995

NO. 31/95-CUSTOMS(NT)

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by Section 156 read with Section 142 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central

Government hereby makes the following rules, namely :—

## CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Customs (Attachment of Property of Defaulters for Recovery of Government Dues) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (i) 'Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962) ;
- (ii) 'Government dues' means any duty or drawback to be recovered from any person or any interest or penalty payable by any person under the Act and has not been paid ;
- (iii) 'Certificate' means the certificate required to be issued by an Assistant Commissioner of Customs under clause (c) of sub-section (1) of Section 142 of the Act ;
- (iv) 'Commissioner' means any person appointed as Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise under the Act ;
- (v) 'Proper Officer' means an officer subordinate to the Commissioner who is authorised by the Commissioner for the purpose of attachment and sale of defaulter's property and for realising the amount mentioned in the certificate ;
- (vi) 'Defaulter' means any person from whom government dues are recoverable under the Act ;
- (vii) Other words or terms used in these rules shall have the same meaning assigned to them under the Act ;

## CHAPTER II PROCEDURE FOR ATTACHMENT OF PROPERTY

3. Issue of Certificate.—Where any government dues are not paid by any defaulter, the Assistant Commissioner of Customs may prepare a Certificate signed by him specifying the amount due from such person and send the same to the Commissioner having jurisdiction over the place in which the defaulter owns any movable or immovable property or resides or carries on his business or has his bank accounts.

4. Issue of Notice.—On receipt of the Certificate mentioned in rule 3 above, the Commissioner may authorise any officer subordinate to him to cause notice to be served upon the defaulter requiring the

defaulter to pay the amount specified in the Certificate within seven days from the date of the service of the notice and intimate that in default, such subordinate officer is authorised to take steps to realise the amount mentioned in the Certificate in terms of these rules.

5. Attachment of the property.—If the amount mentioned in the notice issued in terms of the preceding is not paid within seven days from the date of the service of the notice, the Proper Officer may proceed to realise the amount by attachment and sale of the defaulter's property. For this purpose, the proper officer may arrest or distrain the defaulter's property until the amount mentioned in the Certificate together with the cost of detention is paid by the defaulter.

6. Attachment not to be excessive.—Attachment by arrest or distrain of the property shall not be excessive, that is to say, the property attached shall be as nearer as possible proportionate to the amount specified in the Certificate.

7. Attachment between Sunrise and Sunset.—The attachment of the property of the defaulter by arrest or distrain shall be made after sunrise and before sunset and not otherwise.

8. Inventory.—After attachment of the property of the defaulter, the Proper Officer shall prepare an inventory of the property attached and specify in it the place where it is lodged or kept and shall hand over a copy of the same to the defaulter or the person from whose charge the property is arrested or distrained.

9. Private alienation to be void in certain cases.—

(i) Where a notice has been served on a defaulter under rule 4, the defaulter or his representative in interest shall not be competent to mortgage, charge, lease or otherwise deal with any property belonging to him except with the written permission of the Proper Officer.

(ii) Where an attachment has been made under these rules, any private transfer or delivery of the property attached or of any debt, dividend or other moneys contrary to such attachment, shall be void as against all claims enforceable under the attachment.

10. Share in property.—Where the property to be attached consists of the share or interest of the defaulter in property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the defaulter prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way.

11. Attachment of property in custody of court or public officer.—Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the attachment shall be made by a notice to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held subject to the further orders of the Proper Officer by whom the notice is issued :

Provided that, where such property is in the custody of a court, any question of title or priority arising between the Proper Officer and any other person, not being the defaulter, claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise, shall be determined by such court.

12. Service of notice of attachment.—A copy of the order of attachment shall be served on the defaulter in the same manner as prescribed for the service of order or decision in Section 153 of the Act.

13. Proclamation of attachment.—The order of attachment shall be proclaimed at some place on or adjacent to the property attached by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and on the notice board of the office of the Proper Officer.

14. Property exempt from attachment.—(i) All such property as is by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), exempted from attachment and sale for execution of a decree of a Civil Court shall be exempt from attachment and sale under these rules.

(ii) The decision of the Proper Officer as to what property is so entitled to exemption shall be final.

### CHAPTER III

#### PART A

#### PROCEDURE FOR SALE OF PROPERTY

15. Sale of property.—If the amount mentioned in the Certificate together with the cost of detention of the property is not paid within a period of thirty days from the date of attachment of the property, the Commissioner may authorise the Proper Officer to proceed to realise the amount by sale of the defaulter's property in public auction :

Provided that the Commissioner shall be competent to fix the reserve price in respect of any property of the defaulter to be sold in public auction and order that any bid shall be accepted only on the condition that it is not less than such reserve price.

16. Negotiable instruments and shares in a corporation.—Notwithstanding anything contained in these rules, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the Proper Officer may, instead of directing the sale to be made by public auction, authorise the sale of such instrument or share through a broker.

#### PART B

Special provisions in respect of sale of immovable property

17. Proclamation of sale.—Where any immovable property is ordered to be sold, the Proper Officer shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of the district.

18. Contents of proclamation.—A proclamation of sale of immovable property shall be drawn up after

notice to the defaulter, and shall state the time and place of sale, and shall specify, as fairly and accurately as possible—

- (a) the property to be sold ;
- (b) the revenue, if any, assessed upon the property or any part thereof ;
- (c) the amount for the recovery of which sale is ordered ;
- (d) the reserve price, if any, below which the property may not be sold ; and
- (e) any other thing which the Proper Officer considers it material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of the property.

19. Mode of making proclamation.—(i) Every proclamation for the sale of immovable property shall be made at some place on or near such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the proclamation shall be affixed on a conspicuous part of the property and also upon a conspicuous part of the office of the Proper Officer.

(ii) Where the Proper Officer so directs, such proclamation shall also be published in a local newspaper and the cost of such publication shall be deemed to be costs of the sale.

(iii) Where the property is divided into lots for the purpose of being sold separately, it shall not be necessary to make a separate proclamation for each lot, unless proper notice of the sale cannot, in the opinion of the Proper Officer, otherwise be given.

20. Setting aside of sale where defaulter has not saleable interest.—At any time within thirty days of the sale, the purchaser may apply to the Proper Officer to set aside the sale on the ground that the defaulter had no saleable interest in the property sold.

21. Confirmation of sale.—(i) Where no application is made for setting aside the sale under the foregoing rule or where such an application is made and disallowed by the Proper Officer, the Proper Officer shall (if the full amount of the purchase money has been paid) make an order confirming the sale, and, thereupon, the sale shall become absolute.

(ii) Where such application is made and allowed and where, in the case of any application made to set aside the sale on deposit of the amount and penalty and charges, the deposit is made within thirty days from the date of the sale, the Proper Officer shall make an order setting aside the sale :

Provided that no order shall be made unless notice of the application has been given to the person affected thereby.

22. Sale Certificate.—(i) Where sale of any immovable property has become absolute under these rules, the Proper Officer shall grant a certificate specifying the property sold and the name of the person who at the time of sale is declared to be the purchaser.

(ii) Such certificate shall state the date on which the sale became absolute.

23. Purchaser's title.—(i) Where any property is sold in terms of these rules, there shall vest in purchaser's the right, title and interest of the defaulter at the time of the sale even though the property itself be specified.

(ii) Where immovable property is sold in terms of these rules and such sale has become absolute, the purchaser's right, title and interest shall be deemed to have vested in him from the time when the property is sold, and not from the time when the sale becomes absolute.

24. Irregularity not to vitiate sale, but any person injured may sue.—No irregularity in the conduction of sale of any property shall vitiate the sale but any person sustaining substantial injury by reason of such irregularity at the hand of any other person may institute a suit in a Civil Court against him for compensation, or if (such other person is the purchaser), for the recovery of specific property and for compensation in default of such recovery.

25. Prohibition against bidding or purchase by officer.—No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale under these rules, either directly or indirectly, shall bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

26. Prohibition against sale on holidays.—No sale under these rules shall take place on a Sunday or

other general holiday recognised by the State Government or on any day which has been notified by the State Government a local holiday for the area in which the sale is to take place.

#### CHAPTER IV MISCELLANEOUS

27. Disposal of the sale proceeds.—The sale proceeds of the property of the defaulter shall be utilised in the following manner, namely :—

- (a) the sale proceeds shall first be utilised for meeting the cost of sale,
- (b) the balance shall be utilised for satisfaction of the amount mentioned in the Certificate issued under rule 3 together with the cost of detention of the property;
- (c) the balance, if any, shall be utilised for recovery of any other government dues payable by the defaulter; and
- (d) the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

28. Procedure on death of defaulter.—If at any time after the Certificate has been issued by the Assistant Commissioner of Customs, the defaulter dies, the proceedings under these rules may be continued against the legal representatives of the defaulter, and the provisions of these rules shall apply as if the legal representative were the defaulter.

[F. No. 95-15/94-Cas. VI.]  
T. R. KAPUR, Under Secy.

